असंगठित क्षेत्र के संबंध में इकॉनोमिक सेन्सस

2768. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को अभिलिखित करने वाले "इकोनॉमिक सेन्सस" को प्रकाशित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार सन् 1998 के अंत तक इकोनॉमिक सेन्सस का चौथा और पांचवां संस्करण प्रकाशित करने का विचार रखती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चौथी आर्थिक गणना के परिणामों को दो चरणों में प्रकाशित किया जायेगा। प्रथम चरण में, चयनित महत्वपूर्ण विशिष्टताओं के बारे में त्वरित सारणीयन के आधार पर अखिल भारत स्तर पर अनंतिम परिणामों को जारी किया जायेगा। अनंतिम परिणाम, सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, आन्ध्र प्रदेश को छोड़ कर, जहां पर क्षेत्र कार्य अभी प्रगति पर है, प्राप्त हो गए हैं। ये परिणाम जांचाधीन हैं। दूसरे चरण में, विस्तृत परिणाम राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (1987) के चार अंकीय स्तर तक उपलब्ध हो जाएंगे।

(घ) चौथी आर्थिक गणना के अनंतिम परिणामों को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। पांचवीं आर्थिक गणना अभी सूनियोजित नहीं की गई है।

Absorption of Employees in Centrally Sponsored Schemes

2769. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the procedure followed for permanent absorption of employees on termination of Centrally sponsored schemes in various States and UTs;

(b) number of such employees retained in the State of Assam since introduction of the Centrally sponsored schemes;

(c) whether the liability are permanently shifted to the State; and

(d) if so, action contemplated to support the States for management of these liabilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNINC AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (d) Upon termination, Centrally sponsored Schemes (CSS) cease to be the responsibility of the Government of India. It is, therefore, for the State Government concerned to decide the question of absorption, or otherwise, of the employees under the CSS.

As far as the position in Assam is concerned, the information is being collected and will be laid on the table of the House.

India's Position in Infrastructure

2770. SHRI SANATAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India ranked very low on infrastructure according to a survey done by the National Council of applied Economic Research (NCAER); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) NCAER did conduct a Survey of Multi-national Companies regarding Infrastucture and related issues. Their Survey did not involve any ranking of infrastructure in India *vis-a-vis* other countries. The Senior Managers of Multi-National Companies were asked to rate